'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2019-20-21
WPP Licence No.- U(C)-101/2019-2021
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 30.06.2019
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रकाशक : डॉ. उदित राज, चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-23354841-42

Website : www.aiparisangh.com **E-mail: parisangh1997@gmail.com**

● वर्ष : 22 ● अंक 13 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 16 से 30 जून, 2019

दलित सांसदों की भागीदारी का भ्रम

2014 में जब भारतीय जनता पार्टी जीतकर आयी तब दलित-आदिवासी सांसदों की संख्या उनके पास ज्यादा थी। प्रचारित किया गया कि इन वर्गों का समर्थन पार्टी को ज्यादा मिला और इस बार भी ऐसा ही कहा जा रहा है। 2014 में 84 दलित और 47 आदिवासी सांसद भाजपा के टिकट पर जीत कर आए और इस बार 86 दलित और 52 आदिवासी सांसद जीतकर आए हैं। मुसलमानों के बाद सबसे कम वोट दलित समाज ने भी दिया। उ.प्र. में जाटव समाज 17 प्रतिशत तो अन्य दलित 48 प्रतिशत वोट दिए। अगर मान लिया जाए कि आधी संख्या जाटव की है तो दोनो को मिलाकर 65 होता है। इस तरह से लगभग 32 प्रतिशत ही दलितों का वोट पड़ा जबकि ब्राह्मण का 82, राजपूत का 89, वैश्य का 70 और जाट का 91 है। जितना ही पार्टी के नेतृत्व पर सवर्णों का कब्जा होगा, उतना ही ज्यादा दलित-आदिवासी उस पार्टी में चुनकर जाएंगें।

भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सवर्ण आधारित है, इसलिए दलित-आदिवासी सांसद ज्यादा चुनकर आए हैं। इस तरह की नेतृत्व इन वर्गों से ऐसे प्रत्याशियों का चुनाव करते हैं जो इनकी चमचागिरी करे और वफादार बना रहे। ऐसे दलित-आदिवासी उम्मीदवार को सवर्ण समाज शत्प्रतिशत् समर्थन करता है, क्योंकि वह इनकी परिक्रमा लगाता है और काम भी उन्हीं के अनुसार करता है। पिछड़ों में जो दबंग जातियों है, वे भी सेवादार उम्मीदवार को ही पसंद करते हैं। एक बार जब जब उपरोक्त का समर्थन मिल जाए तो थोड़ा-बहुत जात-बिरादरी का मिल ही जाता है, तो ऐसे में दलित-आदिवासी के लोग ज्यादा चुनकर आ जाते है।। अगर तेज-तर्रार को टिकट दे भी दिया तो खतरा रहता है कि सवर्ण समाज उनका समर्थन करेगा ही। सवर्णवादी मीडिया भी ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में कुछ न कुछ अच्छी बात लिख ही देती है लेकिन स्वाभिमानी अगर होगा तो कुछ न कुछ उसकी खामी उजागर की जाएगी।

कमजोर उम्मीदवार होने की वजह से प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी सवर्ण और दबंग के हाथ में आ जाती है, जो अधिक प्रभावशाली होती है। दबंगई का फायदा भी ऐसे दलित और आदिवासी उम्मीदवार को मिल जाता है। अलीगढ़ के एक सज्जन तीन बार चुनाव सांसद का जीते और उनकी खूबी यह रही है कि अपना गिलास और लोटा लेकर प्रचार करने के लिए निकलते थे और उसी में पानी पीते थे। वे बराबरी पर न बैठकर जमीन पर बैठ जाते थे और सवर्णों के कप एवं गिलास से चाय और पानी नहीं पीते थे, बल्कि अपने गिलास से कहने पर भी नहीं मानते थे और विनम्रता से जवाब देते थे कि वे सेवादार होकर कैसे हिम्मत कर सकते हैं परंपरा को तोड़ने की। ऐसे उम्मीदवारों का समर्थन सरकारी तंत्र से भी मिल जाता है। चुनाव में पैसे के खर्च की बड़ी समस्या होती है। जो

व्यापारी और ठेकेदार होते हैं, पैसा उन्हीं पर लगाते हैं, जो उनकी बात सुने। उन्हें विश्वास रहे कि जीतने के बाद जो वे कहेगें, वहीं होगा। तेज-तर्रार दलित और आदिवासी जीतने के बाद जरूरी नहीं है कि उनके कहने से काम करें।

अधिकतर पार्टियों का नजरिया यही रहता है कि पढ़ा-लिखा और सवाल करने वाले दलित को टिकट न दिया जाए। नेतृत्व को स्वयं भी गवारा नहीं होता कि इन वर्गों के लोग उनसे सवाल-जवाब करें और वे अपने समाज के लिए लड़े, जिससे कि चेतना का विस्तार हो। जो समाज जितना शिक्षित और जाग्रत होगा वह किसी भी पार्टी के लिए चुनौती तो बनता ही है, अगर उनके सरोकारों को संबोधित नहीं किया जाता। उन जातियों का प्रतिनिधित्व संसद और विधान सभाओं में घटता जा रहा है, जो पढ़-लिख गयी हैं और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। उ.प्र. में जाटव समाज से सभी कतराते हैं, क्योंकि वे अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और सच कहा जाए तो चाहे आरक्षण बचाने की लड़ाई हो या उत्पीड़न के खिलाफ, मूलतः लड़ते वही हैं। यह समाज अम्बेडकरवादी हो चुका है और जो अम्बेडकरवादी होगा, वह स्वाभिमानी आवश्य होगा। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में माला समाज को भी इन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और महाराष्ट्र में महार समाज।

जिस तरह से अंधविश्वास, धर्म का प्रयोग और साम्प्रदायिकता राजनीति की दिशा तय करने लगी है, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है और अंत में देश को गर्त में जाना ही है। जो अपने आपको राष्ट्रवाद और विकास की बात करते हैं, उन दलितों और आदिवासियों को पसंद करते हैं, जो प्रायः गूंगे और बहरे होते हैं, क्या इससे देश और समाज का भला हो सकता है? हमारे समाज में सामुदायिक भले की बात सदियों से नहीं रही है और आज भी बहुत कम है और अधिकतर लोग अपना और जाति का भला सोचते हैं और ऐसे में सपना देखना कि यह कभी विकसित देश बन सकेगा, वह पूरा नहीं होने वाला है। जो दलित जातियां शिक्षित एवं स्वाभिमानी हो चुकी हैं, सवर्ण मानसिकता के लोग दूसरी दलित जातियों को उनसे लड़ाने का काम करती हैं और यही नहीं बल्कि पार्टी एवं प्रतिनिधित्व भी उन्हीं को ज्यादा देते हैं। जाग्रत और स्वाभिमानी जातियों का पूर्व में न केवल सरकारी नौकरियों बल्कि राजनीति में भी ज्यादा प्रतिनिधित्व हो चुका है और इसको इस तरह से पेश किया जाता है कि जो दलित जातियां कम शिक्षित और जाग्रत हैं, उनको कहा जाता है कि तुम्हारा हिस्सा कोई और खा रहा है। इन जातियों का लोभी-लालची नेतृत्व और समाज के सीधेपन का फायदा तथाकथित सवर्ण मानसिकता के लोग समय-समय पर उठाते रहते हैं। यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि जिन पार्टियों में ज्यादा दलित-आदिवासी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे इनके बहुतायत के वोट की वजह से है, जो जरूरी नहीं है कि सच ही हो।

- डॉ. उदित राज
पूर्व सांसद एवं
राष्ट्रीय चेयरमैन,
अनुसूचित जाति / जन जाति
संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ
टी-22, अतुल ग्रोव रोड,
कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली-1

परिसंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन 6 व 7 जुलाई को दिल्ली में

06 और 07 जुलाई, 2019 को मावलंकर हॉल, कांस्टीट्यूशन क्लब, नजदीक पटेल चौक मेट्रो, नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें पूरे देश के परिसंघ के पदाधिकारियों, सदस्यों कार्यकर्त्ताओ व शुभचिंतकों सहित बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में विचार किया जायेगा कि आरक्षण पर आए संकट से कैसे निपटा जाए। आरक्षण समाप्ति की ओर है तो निजी क्षेत्र में किस तरह से आरक्षण लागू कराया जाए। इसके अलावा दलितों पर आए दिन होने वाले भेदभाव व अत्याचार की समस्या से कैसे निपटा जाए, आदि मुख्य विषय हैं। इसलिए आप दो दिवसीय सम्मेलन में साथियों के साथ आएं और बैठकर चर्चा में भाग लें। कोई न कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। हम महसूस करते है कि इस समय दलित व पिछड़ा समाज अंधकार में पड़ा है, और उसके अधिकारों पर कुठाराधात हो रहा है। जहां भी मैं जाता हूं सुनने को मिलता है कि आरक्षण खत्म हो रहा है, सिर्फ कागजों में रह गया है, वास्तव में समाप्त हो जायेगा, यदि अब भी समाज घर से बाहर निकल कर आन्दोलन नहीं करेगा तो ये भ्रांतियां हैं कि राजनीतिक सत्ता जब तक न मिले तब तक तो अधिकार नहीं मिल सकते। बाबा साहेब को कोई राजनीतिक सत्ता नहीं मिली थी फिर भी आरक्षण जैसे अधिकार सुनिश्चित कराए। गुर्जर जाट, पटेल और मराठा आदि ने भी सामाजिक आन्दोलन के जरिये आरक्षण लिया है, हम भी समाजिक आन्दोलन के जरिये पहले भी आरक्षण बचाए और आगे भी बचाते रहेंगे।

इस सम्मेलन में हॉल इत्यादि की बुकिंग, खाना की व्यवस्था आदि करने के लिए 500 रू. प्रति व्यक्ति सहयोग राशि के रूप में रखी गयी है। कृपया आने की अग्रिम सूचना **(https://bit.ly/2Dn1Dm0)** पर फॉर्म भर कर अथवा राष्ट्रीय कार्यालय में श्री सुमित मो. 9868978306 या अंकित कुमार मो. 787720495 को फोन करके) दे। सम्मेलन से संबंधित हैंडबिल पेज 4 पर हिंदी में एवं पेज 5 पर अंग्रेजी में छापा जा रहा है, उसे अवश्य पढ़े और अन्य साथियों को भी पढ़ाएं।

- डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिसंघ

मैं परिसंघ का समर्थक क्यों

महामानव तथागत गौतम बुद्ध की समग्र दुनिया में आहलेक छाई हुई है, महात्मा बुद्ध की वाणी से मानव जगत का कल्याण होता रहता है। सम्राट अशोक के बाद महात्मा बुद्ध के कल्याण मार्ग का प्रचार-प्रसार बोधिसत्व डॉ. अम्बेडकर जी ने किया। महात्मा बुद्ध के प्रचारक संतवीर्य कबीर जी थे। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर जी के नक्शेकदम पर मान्यवर काशीराम जी और डॉ. उदित राज जी ने प्रखर पुरुषार्थ से काम किया।

सन 1997 में सरकार द्वारा आरक्षण में संशोधित अध्यादेश पारित किया, उसके बदलाव में डॉ. उदित राज ने खुद की भी परवाह न करके सुपर क्लास- 1 की नौकरी छोडकर अ.जा/ अ.ज.जा के कई संगठनों को जोड़कर राष्ट्रीय लेवल का अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का गठन करके ये अध्यादेश निरस्त करवाए।

अखिल भारतीय परिसंघ ही क्यों? कुछेक लोग और संगठन वाले हमेशा पूछताछ किया करते है कि आखिरकार आप परिसंघ का ज्यादातर प्रचार- प्रसार क्यों किया करते हैं?

उस सवाल का मैं सहज जवाब ये देता हूं की जब सारी संस्थाएँ - एनजीओ सरकार से लाभ ले रहे थे, या लाभान्वित होकर ऐशोआराम और सिर्फ दिखावे के लिए मीटींग वगैरह कर रहे थे, तब परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज, उनके साथी व सहयोगी संगठन दिन रात एक करके, सतत संघर्षरत रहकर अ.जा/ ज.जा. के लोगों के हक के लिए लड़ाई लड रहे थे सतत संघर्ष के परिणामस्वरूप आरक्षण के तीन सुधार अध्यादेश को वापिस करवा सके थे। इसीलिए मैं परीसंघ का प्रखर समर्थक रहा हूं, और अनवरत ये बात प्रचारित करता रहूंगा।

परिसंघ के संघर्ष फलस्वरूप उपलब्धियाँ : परिसंघ का प्रसार अत्यावश्यक है।

परिसंघ की स्थापना से लेकर आज तक की उपलब्धियाँ - भारतवर्ष में परिसंघ के छोटे-बड़े कार्यकर्ता मौजूदा हैं। सभी संविधान के प्रति उत्तरदायित्व हैं, चौकन्ना हैं और हमारे हक की लड़ाई लड रहे हैं।

मेरा पूर्ण आग्रह है कि हमसब अपना मनोबल कायम करके बाबासाहब का कारवाँ और आगे ले जाएं। परिसंघ का प्रसार कैसे बढ़ाया जाय : दरअसल कोई भी संगठन या सत्ता उसके कार्यकर्ता के मनोबल पर आधारित रहता है, मनोबल संगठन के उद्देश्य पर निर्भर रहता है, कार्यकर्ता का मनोबल और संगठन का उद्देश्य संगठन के पदाधिकारियों के विश्वास पर खरा उतरता है। यह सब संगठन के सुप्रीमो की मन्शा पर निर्भर होता है, अतः परिसंघ का उद्देश्य स्पष्ट है, कार्यकर्ता का मनोबल दृढ है और पदाधिकारीगण का विश्वास भी कायम निश्चल है। परिसंघ के सुप्रीमो डॉ. उदित राज जी की मन्शा अटल है, जिसे पूरा राष्ट्र ही नहीं, अपितु संसार के बुद्धिजीवीयों ने उन्हें भारत के दूसरे अम्बेडकर के रूप में माना है।

संगठन के व्याप-विस्तार हेतू ये कर सकते है : हमारे साथ जितने साथी जुड सके उन्हें पहले जोडें। उन सभी को संगठन के उद्देश्य व कार्य समझायें की संगठन ने क्या-क्या किया? फिर उन सब साथीयों को उनके परिवार, ग्राम व जहाँ उनकी पहुंच है वहाँ उसका प्रचार-प्रसार करें। दूसरे संगठन के पदाधिकारीयों से पत्राचार व संपर्क करें।

जिनसे सकारात्मक प्रत्युत्तर मिलता है उनसे मिले और परिसंघ में जोड़ते जायें। परिसंघ का कैडर कैम्प भी लगाना चाहिये। तहसील, जिला स्तर की मीटिंग व कैडर कैम्प करना चाहिए। राज्य अध्यक्ष राज्य स्तरीय अधिवेशन बुलायें और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैडर लेंगे। संगठन में जितना हो सके उतना सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए।

संगठन के पदाधिकारी का कान हाथी जैसा, पेट गणेश जैसा रखना चाहिये, सुनो सबकी, लेकिन किसी से लडाई - झगड़ा नहीं करना चाहिए।

मैंने मेरे हिसाब से परिसंघ को कैसे बढ़ाया जाय ये शब्दों में अंकित किया। उस पर कैसे चलना, कहाँ किस तरह ये सब आप सबको तय करना है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, अनवरत संघर्ष करना पडता है, तब जाकर कुछ हासिल होता है।

- उत्पल कुलकर्णी
गुजरात राज्य
मों. 9898365955

अखिल भारतीय परिसंघ के सामाजिक परिवर्तन की ओर बढ़ते कदम

साथियों जय भीम नमोबुद्धाय जैसा कि बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन किये, बिना राजनीतिक परिवर्तन संम्भव नहीं। इतिहास गवाह है सामाजिक संगठनों एवं सामाजिक आंदोलनों से राजीतिक पार्टियों ने जन्म लिया, सामाजिक आंदोलनों में भविष्य के नेता तैयार होते हैं। मैं बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों खासकर युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अपनी ऊर्जा समाज बचाने में लगाओ, नेता बचाने में नहीं, जब समाज बाबा साहब, फुले, शाहूजी, पेरियार के विचारों का तैयार होगा तो बहुत से नेता समाज में तैयार हो जायेंगे। अब समय आ गया है कि आपसी जातिवाद छोड़कर बाबा साहब के सपनों का भारत तैयार करें तभी हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा।

सामाजिक परिवर्तन की एक कड़ी में, अखिल भारतीय परिसंघ एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा ग्राम खुमान पुर, घासरा अछल्दा, जनपद औरैया मे बुद्ध कथा एवं सामाजिक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, आयोजक कमेटी ने परिसंघ के प्रदेश महासचिव श्री नीरज कुमार चक को बुद्ध का उद्घाटन एवं शुभारंभ करने के लिए आमंत्रित किया।

प्रदेश महासचिव श्री नीरज कुमार चक जी, मण्डल अध्यक्ष डॉ. विशंभर नाथ जी, परिसंघ औरैया के महासचिव श्री सुबोध कुमार बौद्ध जी, संरक्षक परिसंघ औरैया रामदास कठेरिया(बंधू जी), जिला संगठन मंत्री श्री संदीप कठेरिया जी, ब्लॉक अध्यक्ष अछल्दा श्री सुमित कठेरिया जी एवं समस्त परिसंघ द्वारा कार्यक्रम का तथागत बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प एवं माल्यर्पण कर किया गया और भगवान बुद्ध जी के जीवन पर प्रकाश डलाते हुए।

एक बार भगवान बुद्ध से उनके एक शिष्य ने कहा भगवन अब मे आपके द्वारा सिखायी गयी जीवन मरण कें चक्र सें मुक्त कराने वाली विद्या विपश्यना ध्यान को भली भाँति जान गया हूँ, उसे भली भाँति सीख गया हूँ। तो क्या अब में इस विद्या को अपने प्रांत मे जाकर अपने प्रांत कें लोगो को इस विद्या को सिखा सकता हूँ।

तो भगवन ने प्रति उत्तर में पूछा, प्रिय भन्ते तुम्हारे प्रांत कें लोग तो बड़े उग्र स्वभाव के है। बड़े गुसैल है। अगर तुम उन्हें शुद्ध धर्म की बात बताओगे उन्हें शुद्ध धर्म का पालन करना सिखओगे, तो उन्हें ये नयी सी बात लगेगी। वे लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, वे लोग तुमसे गाली गलोच करेंगे, तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, तो तुम क्या करोगे मेरे बच्चे, तो शिष्य ने बड़ा ही प्यारा और समझदारी पूर्वक जवाब दिया, उसने बोला मैं अपने मन में प्राणि मात्र के लिए मैत्री करुणा और प्यार से ये सोचूँगा, कि ये लोग अभी अंधकार मे जी रहे है, इनको शुद्ध धर्म का ज्ञान नही है। मुझे इन लोगो को शुद्ध धर्म का ज्ञान देना है। ये प्राणि कितने भले है, कितने प्यारे है, कोई और लोग होते तो मुझसे हाथा पायी करते मुझे दंडों सें मारते। तो बुद्ध भगवन ने पूछा अगर वो लोग तुमसे हाथा पायी करने लगे, अगर तुम्हें डंडों सें पीटने लगे तो। तो शिष्य बोला तो मे उनको मंगल मैत्री देत्ते हुए सोचूँगा की ये लोग कितने भले है, ये लोग तो सिरफ मुझे दंडों सें पीट रहे है, अगर कोई और लोग होते तों मुझ पर तलवार हथियारों सें हमला कर सकते थे, मेरे अंग काट सकते थे। तों भगवन बुद्ध ने पूछा अगर उन्होने तलवार हथियारों सें तुम्हारे शरीर कें अंग काट दिये तो, तो शिष्य ने उत्तर दिया, में उनको मंगल मैत्री देते हुए अपने मन मे सोचूँगा, की ये लोग कितने भले है, कि इन्होनें तो तलवार हथियारों सें सिर्फ मेरे अंग काटे है, अगर कोई और लोग होते तो तलवार सें मेरा शीश ही काट देते, मेरे प्राण ही हर लेते।

तो भगवन बुद्ध ने पूछा अगर वे तलवार से तुम्हारा शीश काट देंगे तो। तो शिष्य बोला अगर वो मेरा शीश काट देंगे तों मे उनको मंगल मैत्री देते हुए अपने मन मे सोचूँगा की ये लोग कितने भले है, जिन्होनें मेरे प्राण हर लिए, वरना न जानें इस दुखी संसार में कितने ही लोग मन सें दुखी होकर अपने जीवन की लीला समाप्त कर लेते है, आत्म हत्या कर लेते है और एक जघन्य अपराध के भागी बन जाते है। इन लोगों ने तो मेरी मुक्ति कर दी और मुझे ऐसा जघन्य अपराध करने से बचाया।

भगवन बुद्ध ने बड़े प्रसन्न होकर बोला पुत्र तुम शुद्ध धर्म मे पक चुके हो, तुम अब शुद्ध धर्म लोगों को शीखा सकते हो। फिर बड़े प्रसन्न चित कें साथ आशीर्वाद देकर विदा किया, कि जाओ पुत्र जाकर लोगो को शुद्ध धर्म जाकर सिखाओं।

तो मित्रों आपने इस वाक्य से एक सीख जरूर ली होगी, कि चाहे आपकी मंजिल कितनी ही मुश्किल क्युं ना हो, आपका रास्ता कितना ही पथरीला क्यों ना हो, चाहे हिमालय के जितना ही उंचा क्यों न हो, अगर आपके हौंसल बुलंद है, और मन मे मैत्री, करुणा, प्यार है, मन मे विश्वास है, और हौसला बुलंद है, तों आप आज नही तों कल अपनी मंजिल पा ही लोगे। आप कभी अपनी मंजिल की तरफ चलते हुए, थकोगे नही।

इस मौके पर आयोजक समिति द्वारा परिसंघ प्रदेश महासचिव श्री नीरज कुमार चक समेत समस्त पदाधिकारियो का जोरदार स्वागत किया गया, परिसंघ इकाई औरैया की तरफ से बुद्ध कथा आयोजक समिति का आभार प्रकट करते हुए तथागत बुद्ध और उनके धम्म के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई एवं बाबा साहब अम्बेडकर के बताये हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया, साथ ही कथा वाचक कु रजनी बौद्ध अम्बेडकर ने कथा वाचन प्रारंभ किया।

निवेदक-समस्त परिसंघ इकाई औरैया।

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष :	600 रुपए
एक वर्ष :	150 रुपए

संत कबीर दास जयंती पर जानें उनके महान जीवन के बारे में

कबीर एक ऐसी शख्शियत जिसने कभी शास्त्र नही पढा फिर भी ज्ञानियों की श्रेणीं में सर्वोपरी। कबीर, एक ऐसा नाम जिसे फकीर भी कह सकते हैं और समाज सुधारक भी।

मित्रों, कबीर भले ही छोटा सा एक नाम हो पर ये भारत की वो आत्मा है जिसने रूढियों और कर्मकाडों से मुक्त भारत की रचना की है। कबीर वो पहचान है जिन्होने, जाति-वर्ग की दिवार को गिराकर एक अद्भुत संसार की कल्पना की।

मानवतावादी व्यवहारिक धर्म को बढावा देने वाले कबीर दास जी का इस दुनिया में प्रवेश भी अदभुत प्रसंग के साथ हुआ।माना जाता है कि उनका जन्म सन् 1398 में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वाराणसी के निकट लहराता नामक स्थान पर हुआ था। उस दिन नीमा नीरू संग ब्याह कर डोली में बनारस जा रही थीं, बनारस के पास एक सरोवर पर कुछ विश्राम के लिये वो लोग रुके थे। अचानक नीमा को किसी बच्चे के रोने की आवाज आई वो आवाज की दिशा में आगे बढी। नीमा ने सरोवर में देखा कि एक बालक कमल पुष्प में लिपटा हुआ रो रहा है। निमा ने जैसे ही बच्चा गोद में लिया वो चुप हो गया।

नीरू ने उसे साथ घर ले चलने को कहा किन्तु नीमा के मन में ये प्रश्न उठा कि परिजनों को क्या जवाब देंगे। परन्तु बच्चे के स्पर्श से धर्म, अर्थात कर्तव्य बोध जीता और बच्चे पर गहराया संकट टल गया। बच्चा बकरी का दूध पी कर बडा हुआ। छः माह का समय बीतने के बाद बच्चे का नामकरण संस्कार हुआ। नीरू ने बच्चे का नाम कबीर रखा किन्तु कई लोगों को इस नाम पर एतराज था क्योंकि उनका कहना था कि, कबीर का मतलब होता है महान तो एक जुलाहे का बेटा महान कैसे हो सकता है? नीरू पर इसका कोई असर न हुआ और बच्चे का नाम कबीर ही रहने दिया। ये कहना अतिश्योक्ति न होगी कि अनजाने में ही सही बचपन में दिया नाम बालक के बडे होने पर सार्थक हो गया। बच्चे की किलकारियाँ नीरू और नीमा के मन को मोह लेतीं। अभावों के बावजूद नीरू और नीमा बहुत खुशी-खुशी जीवन यापन करने लगे।

कबीर को बचपन से ही साधु संगति बहुत प्रिय थी। कपडा बुनने का पैतृक व्यवसाय वो आजीवन करते रहे। बाह्य आडम्बरों के विरोधी कबीर निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर देते हैं। बाल्यकाल से ही कबीर के चमत्कारिक व्यक्तित्व की आभा हर तरफ फैलने लगी थी। कहते हैं- उनके बालपन में काशी में एकबार जलन रोग फैल गया था। उन्होने रास्ते से गुजर रही बुढी महिला की देह पर धूल डालकर उसकी जलन दूर कर दी थी।

कबीर का बचपन बहुत सी जडताओं एवं रूढीयों से जूझते हुए बीत रहा था। उस दौरान ये सोच प्रबल थी कि इंसान अमीर है तो अच्छा है। बडे रसूख वाला है तो बेहतर है। कोई गरीब है तो उसे इंसान ही न माना जाये। आदमी और आदमी के बीच फर्क साफ नजर आता था। कानून और धर्म की आड में रसूखों द्वारा गरीबों एवं निम्नजाती के लोगों का शोषण होता था। वे सदैव सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध थे और इसे कैसे दूर किया जाये इसी विचार में रहते थे। एक बार किसी ने बताया कि संत रामानंद स्वामी ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लडाई छेड रखी है। कबीर उनसे मिलने निकल पडे किन्तु उनके आश्रम पहुँचकर पता चला कि वे मुसलमानों से नही मिलते। कबीर ने हार नही मानी और पंचगंगा घाट पर रात के अंतिम पहर पर पहुँच गये और सीढी पर लेट गये। उन्हे पता था कि संत रामानंद प्रातः गंगा स्नान को आते हैं। प्रातः जब स्वामी जी जैसे ही स्नान के लिये सीढी उतर रहे थे उनका पैर कबीर के सीने से टकरा गया। राम-राम कहकर स्वामी जी अपना पैर पीछे खींच लिये तब कबीर खडे होकर उन्हे प्रणाम किये। संत ने पूछा आप कौन? कबीर ने उत्तर दिया आपका शिष्य कबीर। संत ने पुनः प्रश्न किया कि मैने कब शिष्य बनाया? कबीर ने विनम्रता से उत्तर दिया कि अभी-अभी जब आपने राम-राम कहा मैने उसे अपना गुरुमंत्र बना लिया। संत रामदास कबीर की विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए और उन्हे अपना शिष्य बना लिये। कबीर को स्वामी जी ने सभी संस्कारों का बोध कराया और ज्ञान की गंगा में डुबकी लगवा दी।

कबीर पर गुरू का रंग इस तरह चढा कि उन्होने गुरू के सम्मान में कहा है,

सब धरती कागज करू, लेखनी सब वनराज।
सात समुंद्र की मसि करु, गुरु गुंण लिखा न जाए।।
यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान।
शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान।।

ये कहना अतिश्योक्ति नही है कि जीवन में गुरू के महत्व का वर्णन कबीर दास जी ने अपने दोहों में पूरी आत्मियता से किया है। कबीर मुसलमान होते हुए भी कभी मांस को हाँथ नही लगाया । कबीर जाँति-पाँति और ऊँच-नीच के बंधनो से परे फक्कड, अलमस्त और क्रांतिदर्शी थे। उन्होने रमता जोगी और बहता पानी की कल्पना को साकार किया। कबीर का व्यक्तित्व अनुकरणीय है। वे हर तरह की कुरीतियों का विरोध करते हैं। वे साधु-संतो और सूफी-फकीरों की संगत तो करते हैं लेकिन धर्म के ठेकेदारों से दूर रहते हैं। उनका कहना है कि-

हिंदू बरत एकादशी साधे दूध सिंघाडा सेती।
अन्न को त्यागे मन को न हटके पारण करे सगौती।।
दिन को रोजा रहत है, राति हनत है गाय।
यहां खून वै वंदगी, क्यों कर खुशी खोदाय।।

जीव हिंसा न करने और मांसाहार के पीछे कबीर का तर्क बहुत महत्वपूर्ण है। वे मानते हैं कि दया, हिंसा और प्रेम का मार्ग एक है। यदि हम किसी भी तरह की तृष्णां और लालसा पूरी करने के लिये हिंसा करेंगे तो, घृणां और हिंसा का ही जन्म होगा। बेजुबान जानवर के प्रति या मानव का शोषण करने वाले व्यक्ति कबीर के लिये सदैव निंदनीय थे। कबीर सांसारिक जिम्मेवारियों से कभी दूर नही हुए। उनकी पत्नी का नाम लोई था, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। वे पारिवारिक रिश्तों को भी भलीभाँति निभाए। जीवन-यापन हेतु ताउम्र अपना पैतृक कार्य अर्थात जुलाहे का काम करते रहे।

कबीर घुमक्कड संत थे अतः उनकी भाषा सधुक्कडी कहलाती है। कबीर की वांणी बहुरंगी है। कबीर ने किसी ग्रन्थ की रचना नही की। अपने को कवि घोषित करना उनका उद्देश्य भी न था। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों का संकलन किया जो 'बीजक' नाम से जाना जाता है। इस ग्रन्थ के तीन भाग हैं, 'साखी', 'सबद' और 'रमैनी'। कबीर के उपदेशों में जीवन की दार्शनिकता की झलक दिखती है। गुरू-महिमा, ईश्वर महिमा, सतसंग महिमा और माया का फेर आदि का सुन्दर वर्णन मिलता है। उनके काव्य में यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुन्दर समावेश दिखता है। भाषा में सभी आवश्यक सूत्र होने के कारण हजारी प्रसाद दिव्वेदी कबीर को "भाषा का डिक्टेटर" कहते हैं। कबीर का मूल मंत्र था, ''मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखिन''। कबीर की साखियों में सच्चे गुरू का ज्ञान मिलता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि कबीर के काव्य का सर्वाधिक महत्व धार्मिक एवं सामाजिक एकता और भक्ती का संदेश देने में है।

कबीर दास जी का अवसान भी जन्म की तरह रहस्यवादी है। आजीवन काशी में रहने के बावजूद अन्त समय सन् 1518 के करीब मगहर चले गये थे क्योंकि वे कुछ भ्रान्तियों को दूर करना चाहते थे। काशी के लिये कहा जाता था कि यहाँ पर मरने से स्वर्ग मिलता है तथा मगहर में मृत्यु पर नरक। उनकी मृत्यु के पश्चात हिन्दु अपने धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान अपने धर्मानुसार विवाद की स्थिती में एक अजीब घटना घटी उनके पार्थिव शरीर पर से चादर हट गई और वहाँ कुछ फूल पडे थे जिसे दोनों समुदायों ने आपस में बाँट लिया। कबीर की अहमियत और उनके महत्व को जायसी ने अपनी रचना में बहुत ही आतमियता से परिलाक्षित किया है।

ना नारद तब रोई पुकारा एक
जुलाहे सौ मैं हारा।
प्रेम तन्तु नित ताना तनाई,
जप तप साधि सैकरा भराई।।

मित्रों, ये कहना अतिश्योक्ति न होगी की कबीर विचित्र नहीं हैं सामान्य हैं किन्तु इसी साधारणपन में अति विशिष्ट हैं। हिन्दी साहित्य के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व कोई नहीं हैं।

https://www-achhikhabar-com/2013/06/23/sant&kabir&das&life&essay&jayanti&in&hindi/

महान आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की प्रतिमा तोड़ने पर आदिवासी समाज के युवाओं ने किया विरोध

झारखण्ड की राजधानी रांची के कोकर में बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर असामाजिक तत्वो द्वारा मुर्ति तोड़ने के विरोध में युवाओं ने जताया विरोध।

'बिरसा तेरा अपमान नहीं सहेगें, नहीं सहेंगें के नारे लगाते हुए जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ता आज प्रातः 11 बजे एसडीएम कार्यालय राजपुर पहुंचे। जहां उन्होंने राष्ट्रपति नाम तहसीलदार भागीरथ वाखला को ज्ञापन सौंपा। नसोवासवाईएफ संगठन के सचिन पटेल व अखिलेश बघेल ने बताया कि झारखंड की राजधानी रांची के कोकर में बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर उनकी आदमकद प्रतिमा है, जिसके एक हाथ में मशाल जबकि दूसरे हाथ में तीर धनुष हैं। दिनांक 13 मई को असामाजिक तत्वों द्वारा द्वेषतापूर्वक उनके धनुष वाले हाथ को तोड़ दिया गया।

सचिन पटेल ने बताया कि जिस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट कर रहे थे, लगभग उसी समय भारत में भी बिरसा मुंडा अंग्रेजों, जमीदारों को शासकों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ चुके थे। उन्होंने अंग्रेजों, जमीदारों के खिलाफ संघर्ष किया है। साथ ही उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों को अपने मूल पारंपरिक आदिवासी धार्मिक व्यवस्था, संस्कृति एवं परंपरा को जीवंत रखने की प्रेरणा दी। आदिवासी समाज का जो अस्तित्व एवं अस्मिता बची हुई है, तो उसमें बिरसा मुंडा का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए पूरे देश का आदिवासी समाज उन्हें भगवान के समान पूजता है। ऐसे में बिरसा मुंडा की प्रतिमा के साथ जो कायराना हरकत की गई है। उससे पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि मुर्ति को तोड़ने वाले लोगों को जल्द पकड़कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आगे से देश के महापुरूषों की मुर्ति के साथ इस तरह की घटना ना घट सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान अखिलेश अक्कू पटेल, जयस जिला उपाध्यक्ष महेश भाबर, परमानंद मुजाल्दे, दिनेश चौहान, पंकज गोरे, नसोसवायएफ ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश बघेल, नंदिनी गोरे, लक्ष्मी गोरे, वंदना सानियर, नंदिनी निगवाल, रिंगेश रावत, प्रवक्ता विजय जमरे, जिला अध्यक्ष आइटी सेल मुन्ना मोरे, आदिवासी एकता परिषद के राजाराम कनासे दादा, मुकेश चौहान, राहुल डोडवे, अनिल बडोले, इंद्रपाल वास्कले, अर्जुन चौहान, राजा उचवार, रंजीत आवासे, महेश रोमडे, साजित मंसुरी, विजय रोमड़े, सचिन निंगवाल, विशाल निंगवाल, महेश, प्रकाश वास्कले, दशरथ कन्नोजे, कमल अलावे, सुरज कोठारी, विनोद राठौड़, सावन सोलंकी, अश्विन निंगवाल, रवि आवासे, सुखलाल गोरे, कन्हैया चौहान, आदि कार्यकर्ता मौजुद थे। उक्त जानकारी मिडिया प्रभारी राहुल डोडवे ने दी।

सचिन पटेल,
इंदोर सभांग अध्यक्ष,
नसोसवाईएफ
9691515815

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ

6 एवं 7 जुलाई को परिसंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में

समाज चाहता है कि उसके लिए नेता लड़े और मैंने वही किया तो भाजपा और आर.एस.एस. ने मेरा टिकट काटकर मुझे वंचित किया कि इस बार भी गलती से मैं संसद में न पहुंच जाऊं। अब यह समाज के हाथ में ही है कि वे मुझे दंडित करने में कामयाब हो पाते हैं अथवा नहीं। यदि मैं समाज के हित में न बोलता तो मंत्री होता, कम से कम टिकट की तो कोई चिंता न होती। बड़े बंगले सहित तमाम तरह की सुख-सुविधाएं और संसाधन होते लेकिन आज परिसंघ का कार्यालय चलाना भी भारी पड़ रहा है। दलित समाज के प्रति मेरा समर्पण एवं संघर्ष को भाजपा ने कभी भी पसंद नहीं किया और उन्होने मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की लेकिन मैं अंतिम सांस तक समाज के हित के लिए लड़ता रहूंगा। यद्यपि मनुवादियों ने मुझे संसद के अंदर लड़ाई लड़ने से रोकने का प्रयास किया लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे लोग मुझे संसद के बाहर लड़ाई लड़ने के लिए साथ देने में पीछे नहीं हटेगें जो ज्यादा लाभप्रद है। देखना है कि अब समाज साथ देता है कि भाजपा एवं आर.एस.एस. मुझे दण्डित करने में सफल होते हैं ? जिन गलतियों के कारण मेरा टिकट कटा उनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं :-

- प्रधानमंत्री की मौजदूगी में संसद में आरक्षण खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार को कटघरे में खड़ा किया जो शायद कोई न कर सका।
- निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए संसद में बिल पेश किया।
- 2 अप्रैल, 2018 को भारत बंद का समर्थन ही नहीं बल्कि परिसंघ ने इसका नेतृत्व करते हुए पूरे देश में भाग लिया।
- दिल्ली भाजपा द्वारा दलित भोज का विरोध किया और कहा कि यह सब करने से इनका वोट नहीं ले सकते बल्कि इन्हें भागीदारी दो।
- सबरीमाला मदिर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ा हुआ और भाजपा ने महिलाओं को मंदिर में प्रवेश का विरोध किया तो मैंने एक अम्बेडकरवादी होने के नाते इसका समर्थन किया।
- गुजरात हाई कोर्ट के न्यायधीश ने आरक्षण व भ्रष्टाचार को देश की बर्बादी का कारण बताया तो संसद में दो बार मैंने ही विरोध किया और अंत में फैसले से वह लाइन हटाया गया।
- 2015 में बंगलौर में भाजपा कार्यकारिणी में ईसाईयों पर अत्याचार का विरोध किया।
- सभी सांसदों एवं नेताओं की मौजूदगी में 2014 में आर.एस.एस. और भाजपा द्वारा समरसता के स्थान पर समतामूलक समाज बनाने की आवाज उठायी।
- सहारनपुर में जेल में बंद चंद्रशेखर उर्फ रावन की रिहाई की मांग संसद में मैंने उठाया, कोई अन्य दलित सांसद ऐसा करने का साहस न कर सका।
- लगातार आरक्षण और खाली पदों पर भर्ती का मुद्दा उठाता रहा।
- मैंने सवाल किया कि लाभ वाले सार्वजनिक उपक्रमों को क्यों बेंचा जा रहा है, इससे सबसे अधिक नुकसान दलितों का ही है
- सरकार द्वारा दलित एवं आदिवासियों के लघु उद्योगों से 4 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा की खरीद की योजना को न लागू करने के लिए निरंतर विरोध किया।
- रोहित वेमुला, उना आदि घटनाओं के लिए सरकार की निष्क्रियता पर आवाज उठाई।
- स्टैंड-अप इंडिया के तहत सवा लाख बैंक शाखाओं से दलितों को लोन देकर व्यापारी बनाने की योजना का पर्दाफाश किया। केवल 6 प्रतिशत बैंक शाखाओं द्वारा ही अजा/जजा को लोन दिया गया।
- SCP/TSP प्लान का दर्जा खत्म करके सामान्य कर दिया अर्थात इसके अंतर्गत आबंटित राशि कहीं भी दुरूपयोग की जा सकती है।
- कई बार आवाज उठाई कि उच्च पद जैसे सचिव, कुलपति आदि में दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही ?
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वजीफा की राशि क्यों रोकी गयी, इससे करोड़ो बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ा।
- दिल्ली विश्वविद्यालय के नेतृत्व में 13 प्वाइंट रोस्टर के विरोध में विद्यार्थी एवं शिक्षक के विशाल प्रदर्शन का न केवल संबोधन किया बल्कि उनके साथ खड़ा रहा। मोदी जी और अमित शाह के डर से क्या कोई और सांसद ऐसा करने की सोच सकता है ?

विभिन्न स्वतंत्र एजेंसियों के सर्वे के आधार पर सांसद के रूप में उत्कृष्ट कार्यो के लिए मुझे श्रेष्ठ सांसद, बेजोड़ सांसद एवं पूरे देश में द्वितीय सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में सम्मानित किया गया, जो बहुजन समाज के लिए गर्व की बात है। पिछले 70 सालों शायद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसी एजेंसियों द्वारा दलित वर्ग से किसी सांसद का चयन हुआ हो।

मैं चाहता हूँ की काम, नतीजा, योग्यता, ईमानदारी और समर्पण के आधार पर समाज नेता माने। अगर मुझसे अच्छा कोई और काम करने वाला हो तो समाज उसका नाम बताए या मेरा साथ दे। अभी तक भावना, जाति और नाम पर नेता समाज ने माना उसका परिणाम हुआ की आरक्षण लगभग समाप्त हो गया और काम करने वालों का अब भी समाज साथ नहीं दिया तो भूल जाओ कि मान, सम्मान और अधिकार अब बचने वाला है। माला-मादिगा और चमार बनाम मै चमार की लड़ाई से हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगें। भाजपा का हिन्दू राष्ट्र का सपना अब साकार हो चुका है। राष्ट्र को किसी से कोई खतरा नहीं है लेकिन ऐसा प्रचारित किया गया कि हमारे लोग भी भावना में आकर ऐसा मान बैठे और राष्ट्र बचाने के नाम पर भाजपा को वोट दिया। यदि हिन्दू राष्ट्र का इनका सपना साकार हुआ तो इसके लिए हमारे स्वार्थी, जातिवादी एवं अहंकारी दलित एवं पिछड़े ही जिम्मेदार हैं।

6 एवं 7 जुलाई, 2019 को सुबह 10 बजे से परिसंघ का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मावलंकर हॉल, रफी मार्ग, नजदीक पटेल चौक मैट्रो, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यदि आप वास्तव में मेरे साथ हैं तो इस सम्मेलन में अवश्य भाग लेगें। शायद यह संविधान एवं आरक्षण बचाने का अंतिम अवसर है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप 6 जुलाई, 2019 को प्रातः 10 बजे साथियों सहित सम्मेलन में पहुचेगें और 7 जुलाई को सायं 4 बजे तक इसमें भाग लेगें। अब तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों से संसाधन एकत्रित करके भाग लेने वालों के खाने एवं ठहरने की व्यवस्था कराने में असमर्थ हूं, इसलिए सम्मेलन हेतु 500 रुपये की सहयोग राशि रखी गयी है। अग्रिम सूचना हेतु https://bit.ly/2Dn1Dm0 पर जाकर संबंधित फार्म भरें अथवा राष्ट्रीय कार्यालय में अंकित कुमार (7827720495) या सुमित कुमार (9868978306) से सम्पर्क करें।

- डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय चेयरमैन

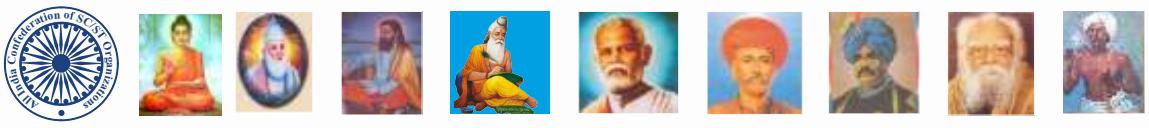

All India Confederation of SC/ST Organisations (Parisangh)

National Convention on 6th & 7th July, 2019 at Mavalankar Hall, Constitution Club, Near Patel Chowk Metro, New Delhi.

Our SC, ST and OBC people want that political leaders fight for them and I tried to fulfil their wish and for this the BJP and RSS punished me by denying the ticket to Lok Sabha,so that I could not reach to the Parliament. Now it is in the hands of SC/STs whether to allow them to punish me. If I had not fought, I could have enjoyed Ministerial position and the ticket would not have been a problem. All possible luxuries and facilities like big bungalow and resources would have been at my command and now it is even becoming diffcult to run Parisangh's office . My commitment and struggles were strongly disliked by the BJP and they decided to silence my voice,but they can not do so till my last breath of life. If Manuvadis have denied the right to fight in the Parliament, I hope my people will give support to fight outside Parliament, which will be more beneficial . Following were important "faults" for denial of the ticket to me:-

Please fill up the form for participation Click **https://bit.ly/2Dn1Dm0**

- In the presence of the Prime Minister, I raised my voice against the Supreme Court,which is killing reservation,and criticized the govt. No MP could have dared to do so.
- Introduced a Private Member Bill in Parliament for reservation in Pvt. Sector.
- Not only supported Bharat Bandh on 2nd April, 2018 but Parisangh participated in it at All India level.
- When Delhi BJP Unit organized Dalit Bhoj, it was challenged by me by issuing the statement that no longer it will help in garnering their votes but they need share in power and governance.
- BJP opposed Supreme Court judgment which empowered women to enter the Sabrimala Temple and as an Ambedkarite, I rose against it.
- A judge of Gujarat High Court held reservation and corruption responsible for backwardness of the country and it was I who raised voice against him strongly in the Parliament,with the result that those lines were expunged.
- In the National Executive meet of BJP at Bangalore, I voiced the concern about attack on Christians.
- In the first meeting of newly elected MPs, in 2014, it was objected by me that why not Samtamulak Samaj (casteless society) instead of Samrasta.
- No MP raised the question to release Chandrashekhar Rawan from the Jail except me.
- Number of times questions were raised at why backlog vacancies were not being filled.
- I questioned why public sector undertakings were being disinvested and sold.
- Why a govt. policy to procure 4% goods and services from SC/ST could never be achieved beyond .4% ,I asked.
- Never failed to raise the questions on atrocities on Dalits,be it Rohit Vemula case or Una or else where.
- Under the policy of stand-up India ,1.25 lacs Bank Branches were to give loans to dalits to become entrepreneurs, but only 6% was achieved.
- SCP and TSP were stripped of special status as a sub-plan and treated as a normal budget so that it did not become binding to incur expenses on SC/STs..
- Why there was no representation as Vice-Chancellors, Secretaries and such important positions from SC, ST, OBCs ?
- Why the Ministry of Social Justice and Empowerment denied scholarships which affected education of crores of SC, ST and OBC students ?
- I participated in various agitations and conferences organized by different organisations like Delhi University Teachers Association and other organisations and parties who opposed 13 point roster and other anti SC/ST/OBC policies. Of course, how could RSS and BJP have tolerated my such actions?

I also became pride for the Bahujan Samaj by becoming bejod saansad(unparalleled MP),Shreshth saansad(best MP) and second best performing MP, as per ratings of various independent agencies.To my mind no one from SC/ST was chosen like this by upper caste agencies in 70 years .

I want that leaders should be chosen on the basis of their work, honesty, results and not on the basis of caste and region,etc. Lesson should be learnt that Mala-Madiga and Chamar vs Non-Chamar fight has nearly finished us.If there is better person than me, I am ready to follow him,otherwise give me full support. The wishes of BJP to have Hindu Raj and save the nation, have been fulfilled now .There was no threat to the nation but even our people were emotionalized to believe it and to vote for the BJP.If Hindu Raj has come back, selfish, casteists, egoists dalits and OBCs are responsible.

With heavy heart, I am giving the call to participate in the National Convention on 6th & 7th July, 2019 at Mavalankar Hall, Constitution Club, Near Patel Chowk Metro, New Delhi. Perhaps this is the last chance to save the Constitution and Reservation and I expect that you will reach on 6th July with some missionary friends at 10 AM and remain till 4 PM of 7th July, 2019. Now I can't afford to get funds from upper castes to arrange food and to incur other expenses for you, so small contribution of 500/- is required.

-Dr. Udit Raj, National Chairman

AlParisangh AlParisangh 9899766443 parisangh1997@gmail.com All India Parisangh www.aiparisangh.com

धड़ाधड़ हो रहे निजीकरण से सबसे अधिक नुकसान दलितों एवं पिछड़ों का ही है, फिर भी देश में कहीं से कोई विरोध के स्वर मुखर नहीं हो रहे हैं। अभी तक हमारे जीवन-स्तर में जो थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, वह आरक्षण के कारण ही हो सका है। चूंकि निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, इसलिए हमारी दुर्दशा क्या होगी, अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है : डॉ. उदित राज, रा. चेयरमैन, अजा/जजा परिसंघ

मोदी सरकार के शुरुआती 100 दिनों में होगे बड़े बदलाव, 42 सरकारी कंपनियों का होगा निजीकरण

दैनिक जागरण में 31 मई, 2019 को छपी खबर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोबारा सत्ता में आने के शुरुआती 100 दिनों के भीतर कई बड़े आर्थिक बदलाव हो सकते हैं। यह जानकारी नीति आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। सरकार के इस कदम से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार की तरफ आकर्षित होंगे। यह भी संभव है कि सरकार एयर इंडिया सहित 42 सरकारी कंपनियों का या तो निजीकरण करेगी या बंद करेगी।

जिन कंपनियों का निजीकरण/बंद करने की बात की जा रही है, उनमें प्रमुख हैं –

क्र. संख्या	मंत्रालय/कंपनी/ विभाग का नाम सरकार की	मंजूरी की तिथि
	भारत उद्योग विभाग	
1.	तुंगभद्र स्टील प्रोडक्ट्स लि.	22.12.2015
2.	एच.एम.टी. वाचेज लि.	06.01.2016
3.	एच.एम.डी. चिनार वाचेज लि.	06.01.2016
4.	एच.एम.टी. बेअरिंग लिं.	06.01.2016
5.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	28.09.2016
6.	ट्रैक्टर यूनिट ऑफ एच.एम.टी. लि.	27.10.2016
7.	कोटा यूनिट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल लि.	30.11.2016
	पोत परिवहन मंत्रालय	
8.	सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांस्पोर्ट का. लिं.	31.08.2016
	औषधि विभाग	
9.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मासुटिकल्स लि.	28.12.2016
10.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मासुटिकल्स लि.	28.12.2016
	पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय	
11.	IOCL-CREDA Biofuels Ltd.	22.03.2007
12.	CREADIA HPCL Biofuels Ltd.	22.03.2017
	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	
13.	अंडमान एवं नीकोबार द्वीपसमूह वन एवं प्लेटिनम विकास निगम लि. (पोर्ट ब्लेयर)	16.08.2017
	रेल मंत्रालय	
14.	भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कं. लि.	23.08.2017
15.	बर्न स्टैंडर्ड कं. लि.	04.04.2018
	रासायन एवं पेट्रो-रासायन विभाग	
16.	हिन्दुस्तान आर्गनिक केमिकल्स लि.	17.05.2017
	के सभी विभागों को बंद करना	
17.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग का. लि.	10.10.2018
18.	बर्ल्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लि.	10.10.2018
	वाणिज्य विभाग	
19.	एस.टी.सी.एल. लि.	13.08.2013

इसी तरह की अन्य कंपनियों का भी निजीकरण करने की योजना है।

स्पीड और सुरक्षा के नाम पर रेलवे निजीकरण की ओर

रेलवे के अधिकारी सवालों को लेकर फिलहाल जवाब देने से बच रहे हैं पर रेलवे ने मसौदा तैयार कर लिया है। कुछ मुद्दों पर बात खिंच भी सकती है पर प्राथमिकता तय है और उसको दिशा देने की कोशिश है।

25 जून, 2019 को एनडीटीवी खबर के अनुसार रेलवे ने

100 दिनों का खाका तैयार कर लिया है। एनडीटीवी को मिले डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि रेलवे निजीकरण की तरफ बढ़ने वाली है। साथ ही सुरक्षा और गति बढ़ाने पर भी ज़ोर रहेगा और टिकट में हो रहे घाटे से उबरने को लेकर सब्सिडी छोड़ने का विकल्प भी यात्रियों को दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि रेलवे ने अगर 100 दिन की अपनी योजना पर ठीक से अमल किया तो तीन महीने बाद दिल्ली और मुंबई के बीच 160 किलोमीटर की स्पीड से भी ट्रेनें चलेंगी। 15.5 घंटे का मौजूदा सफ़र 10 घंटे का रह जाएगा। इसी तरह दिल्ली हावड़ा के बीच का सफ़र 17 घंटे से घट कर 12 घंटे रह जाएगा। ये दावे कितने सफल होगें, यह तो समय ही बताएगा लेकिन इस कार्य योजना में सबसे अहम मसला निजीकरण का है। इसके मुताबिक अब तक मंत्रालय की हरी झंडी पर दौड़ने वाली रेल प्राइवेट प्लेयर्स भी दौड़ा पाएंगे। रेलवे इसकी संभावना तलाशने में जुट गई है। ✦✦✦

तीन लाख करोड़ की संपतिवाला बीएसएनएल 950 करोड़ में बिक रहा है, अंबानी-अदानी है प्रबल खरीददार

पटना : मुल्क के आर्थिक हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे है। देश की सबसे बड़ी सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के पास अपने 1 लाख 70 हजार कर्मचारियों को जून महीने की तनख्वाह देने के लिए पैसे नही है कंपनी ने एक बयान जारी कर के कहा है कि कैश की कमी के चलते जून के लिए लगभग 850 करोड़ रुपये की सैलरी दे पाना मुश्किल है इससे पहले भी इसी साल लोकसभा चुनाव पूर्व ऐसी स्थिति बन चुकी है लेकिन तब जैसे तैसे कर के इन कर्मचारियों की तनख्वाह दे गयी, लेकिन अब पानी सर के ऊपर से गुजरने वाला है।

कुछ दिन पहले ही बीएसएनल कर्मचारियों की एक बड़ी संस्था 'दि आल इंडिया ग्रैजुएट इंजीनियर्स एंड टेलीकॉम आफिसर्स एसोसिएश ने प्रधानमंत्री को इस बारे में पत्र लिखा था पत्र में प्रधानमंत्री से कंपनी के नकदी संकट को दूर करने के लिये बजट समर्थन दिये जाने का अनुरोध किया गया था। पत्र में उन्होंने जो पॉइंट उठाए है वह गौरतलब है उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि 'बीएसएनएल ने 2014–15 में 672 करोड़ रुपये, 2015–16 में 3,885 करोड़ रुपये और 2016–17 में 1,684 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ दर्ज किया था'। यदि यह बड़ा

लाभ कमाने वाली कम्पनी थी तो पिछले 2 सालों में अचानक ऐसी कौन सी आपात स्थिति आ गयी कि इतनी बड़ी कम्पनी को अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लाले पड़ गए हैं।

पत्र में यह भी कहा गया है कि 'बाजार बिगाड़ने वाली परिस्थितियों के चलते बीएसएनएल सहित पूरा दूरसंचार क्षेत्र दबाव में आया है। इसके बावजूद बीएसएनएल की बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हो रही है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद बीएसएनएल आत्मनिर्भर है और उस पर कोई कर्ज बोझ नहीं है। यह दूसरी दूरसंचार कंपनियों के एकदम उलट स्थिति है जो कि भारी कर्ज बोझ तले दबी हैं। दूरसंचार क्षेत्र की अन्य कंपनियों बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कर्ज बोझ तले दबी हैं'। लेकिन इन सबके बावजूद सिर्फ अपने मित्र पूंजीपति की एक कंपनी को फायदा पुहचाने के लिए लाखो कर्मचारियों के परिवारों को दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर किया जाएगा। यही तो है 'सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास का खून।

https://dailybihar.com/en_US/bsnl/?fbclid=IwAR1uDG5NTxEBObAb2gfKQb79X6QT3P6J9OAn3avEfnZBJwkw_abzK8cnIAg

✦✦✦

At 8.8%, joblessness higher in state than in Punjab, HP, J&K

Haryana's unemployment rate also exceeds 6.5% national average, says survey

Bhartesh Singh Thakur
Tribune News Service

Haryana has an unemployment rate of 8.8 per cent in the 15-59 age group, according to Periodic Labour Force Survey (PLFS) of the Ministry of Statistics and Programme Implementation. The unemployment rate is higher than neighbouring states. The survey was released after the new government came to power at the Centre.

Among the males in the age group of 15-59, the unemployment rate is 8.4 per cent and among the females it is 11 per cent in the state. In Himachal Pradesh, the overall unemployment rate is 6.2 per cent, in Punjab it is 8.3 per cent and in Jammu and Kashmir it is 5.2 per cent. The national average is 6.5 per cent.

Diploma holders more affected

In the age group of 15 years and above, the unemployment rate is 8.4% in Haryana. In this age group, the unemployment rate is the highest (21.2%) among diploma or certificate holders, followed by 17.2% among graduates and 12.9% among those who have studied up to higher secondary.

Unemployment rate
8.3% in Punjab
6.2% in Himachal
5.2% in J&K
(15-59 years)

The unemployment among those with postgraduation or higher degrees is 8.9%. However, those who are not literate and have studied up to the primary level, the unemployment rate is 2% and 5.5%, respectively.

In Punjab, the unemployment is higher among diploma holders (20%) followed by those with postgraduation degrees and above (18.4%) and graduates (13.1%).

No paid leave

Among the regular wage employees in Haryana, 57.5% are without any written job contract, 51.6% do not get paid leave and 53.4% are without any social security benefits like provident fund or pension, gratuity, healthcare and maternity benefit.

There are 41.6% of employees who neither get paid leave nor have a written job contract and social security benefits. The figure of such employees in Punjab stands at 52.2%, but in Himachal it is 34.9%.

https://www.tribuneindia.com/news/haryana/at-8-8-joblessness-higher-in-state-than-in-punjab-hp-j-k/786038.html

✦✦✦

PRESS CONFERENCE ALL INDIA CONFEDERATION OF SC/ST/OBC ORGANISATIONS J&K UNIT

JAMMU: 18.06.2019: Under the aegis of All India Confederation of SC/ST/OBC Organizations, Jammu Unit, a press conference was held under the stewardship of Sh. R. K. Kalsotra, State President wherein the Confederation asked for stringent action against those responsible for perpetuating the ignominious caste system in official communications for criminal misconduct so that the discrimination abates and the people from such communities are reassured about stoppage of continuous discrimination & atrocities.

Mr. Kalsotra also submitted a memorandum about the feelings of Reserved category employees & their genuine grievances that day in & out caste is being quoted in routine orders which is unnecessary & invites caste based humiliation for them in offices & society as a whole. He further said that mentioning of caste against the names of officials appears to be a retrograde step. It is psychologically depressing for those who are already counted as weaker sections of the society and figured low in the superficially created social hierarchy. Instead of obliterating caste and implementing the Constitution in letter and spirit, it will have disastrous effect and may further sharpen the already existing dissensions in society and it will be a progressive step in case necessary directions to all concerned in the govt. is issued whereby it is directed not to mention caste in any of the govt. orders where it is neither required nor serves any useful purpose.

Mr .Kalsotra further lashed out at the Department of Social Welfare which is a Nodal Agency to safeguard the interest of reserved categories but has abjectly failed to perform its legitimate duty. He said that persons belonging to Reserved Category are being targeted & harassed on the basis of caste & the concept of caste discrimination is being propagated at each level, whether at the level of transfers, postings or promotions. No adequate representation is provided to the reserved category officers in significant field postings but on the contrary, caste tag is being pasted unnecessarily upon the employees belonging to these persons in matter of transfers/postings. Orders are intentionally being issued by the various departments, so that persons belonging to reserved categories are demoralised and are introduced at the new place of posting by their caste. One such example is where the Rural Development Department vide order No. 178-RD & PR of 2019 dated 30-05-2019 has transferred officers by conveying the caste/category of employees belonging to reserved categories. Next, under the "Back to village" programme GAD has also, vide order No.682-GAD of 2019 dated 14.06.2019 issued an order by describing castes of officers, so that these officers are introduced in Panchyat by their caste.

Mr. Kalsotra further lamented that no government in the country, at the centre or at the state level, has ever acted in such manner in the past but these issues are being propagated from past one and a half year by some administrative departments including GAD of the state. These malafide actions end up in propagating caste related inequalities & a feeling could emerge in them after knowing that the high-ups have not issued any advisory and it may appear that they too are in favour of propagating the caste system. He said that persons who are socially and educationally backward have already suffered the scourge of casteism and this blot that stigmatizes the populace belonging to reserved categories, which was inflicted upon them for millennials together has to be obliterated and the state should follow the constitution to provide governance to the common man rather than propagating the introduction of its employees with un-social tags. The civil list of GAD officers displayed on website of GAD, unnecessarily display the castes when it is of no fruitful use but instead of obliterating caste and implementing the Constitution in letter and spirit, it will have deleterious effect and may further sharpen the already existing divisions in the society.

It was elaborated that Governor has been approached as the last ray of hope but in case no action was taken at his end, then the Confederation will adopt the strategy of 'Educate, Organize, Agitate' to raise a mass movement among the general public for rectification of the wrong steps being taken by the government

Others who spoke were Molvi Shah Mohd, Shashi Syal,Ashwani Bhagat, Azam Melu, Kuldeep Mehra, Rattan LAL Bhagat, Hari Ram Bhagat, Sham LAL,,Tilak Raj & others

- R. K. Kalsotra
State President

✦✦✦

एक बार जरूर देखाना चाहिए आर्टिक 15

आर्टिकल 15' का हर एक सीन वास्तविक नजर आता है। वह सीन जब दोनों लड़कियों को पेड़ से लटकता दिखाया जाता है, वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहीं एक सीन में उन वर्कर्स को दिखाया गया है, जो गटर और गंदे नालों में नंगे उतारकर उनकी सफाई करते हैं, ताकि हम जैसे लोगों को गंदगी का सामना ना करना पड़े। अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो वह सीन भी आपको हिला देगा। समझ आएगा कि अगर ये वर्कर्स अपना काम ना करें, तो देश के क्या हालत हो सकते हैं।

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 22 ● Issue 13 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 16 to 30 June, 2019

GUILTY WILL ALWAYS BE THE SC'S /OBC'S

The recent Lok-Sabha Electionsconcludes the final of analysis of the caste based voting with respect to the parties!

This is not a new phenomenon and since decades such exercises are undertaken and what is startling and painstakingis,that always the castes belonging to the OBCs and SCs , like Jatavs, Kurmis, Yadavs, Mahars, Malas, Madigas, Matangs, Satnamis, Balmikis, Meghwals and Bairwas are under scrutiny as to which political party have they voted. Wherever,party gets the majority vote by these backward caste, it is labelled as 'Caste Politics'. 1980 onwards various regional parties have come into existence and the caste has gone with their leaders and this has been the fodder for Journalism, research and analysis. If the SCs and the OBCs do not cast their vote to the upper-caste based leadership, then they are scrutinized and criticized. Researchers, intellectuals and reporters hardly monitor the voting of the Brahmins, Thakurs and Vaishyas.Ever since the OBC,ST and the SC's had started following their caste leaders, part of the politicshas become castistsas pointed by the upper castes.

It is hardly penned about the voting behaviour of the upper-castes. The print media to the electronic media start their own survey in analysing the voting trend of the OBC,SC and the other backward castes before the elections. It is termed as "Vote –Bank Politics" when the majority vote of the Dalits,OBCs and SCs are casted in the support of their caste leader. Discussions, debates, seminars etc. startsabout the their voting preferences and behaviour and contrary, the upper castes rarely fall under the scrutiny of the medias.The voting analysis about the voting pattern of the 'Upper Castes in UP Lok Sabha is eye opening. 89% of the Thakur's voted went for BJP, Brahmin's vote share went beyond 82% and more than 70% Baniyas also joined the upper caste voting trend. No report nor allegations were highlightedby the media in pointing out the 'Caste Politics' played by the BJP. Had it been in the case of DSP, SP, in no time their voting preference would have been branded as 'Castists'. If the Dalit's and OBC's vote for the parties led by upper caste, they will be absolved of being castists.The question that stands un-answered till day is, that whymost of the political parties in the country are dominated by the Leaders of the Upper-Caste'only. The Brahmins leadership is accepted by the Kshatriyas, Dalit's, OBCs, Tribal all are mostly minorities and therefore most of parties are Brahmin based. Thakurs are not that privileged but below to them in the hierarchy all accept their leadership. Banya's are little bit at dis-advantage as above them, Brahmins and Thakurs, have some reservations. The OBC's have a dis-advantage of getting the support of the Brahmins, Thakurs, Vaishyas and a few OBCs and Dalits prefer upper caste leadership because of mind-set. Dalit based leadership politics are used to win the election only by pooling in the vote of the backwards castes. The involvement of the Dalits in the politic war game is just for the motive of vote and this the only reason of lending support to the Dalits, "Benefits of the Caste Politics". Even some OBC's and Dalits caste may be out of comfortable zone to support the Dalits leadership. Minorities are at most worst state, hardly anyone will support them till gain is not guaranteed.

The Times Of India has carried out the evaluation of the merit list in the medical admissions. The government medical colleges have 39,000 seats and 17,000 other seats which are filled either by the NRI quotas or capitation fees.The study of 57,000 NEET qualified stock was put under scrutiny and it was found that the merit of the general category in the government medical colleges was at 448 and for the SC's it was 398. In 308 private colleges where admission is short under the NRI quota or by way of capitation fees the merit is at 211. It has never been noticed that the doctors produced through NRI and capitationfees have no merits or are of inferior quality. Comparing the merit of NRI and capitation fees vis-à-vis,the SC's candidates, their merit is more than 200% and yet whispering can be heard that who will get treated from reserved category doctors. There are few reserved category of doctors who try having their personal clinic and but face the stigma of merit.

IIT has conducted a study to ascertain about the main factors that helps in getting the admission done. It was found that most of entrants belong to professional's family like doctors, engineers and officers. There entrants are from bigger cities where the coaching facilities and paraphernalia's are available. Most of them come from good economic background and strong support of social capital and are from good schools. These facts when are takeninto consideration in comparison with the SC/STs aspirants, they are not less meritorious than general category.

Most of the time whether it is voting behaviour or admission in educational institution or in the government jobs, the scrutiny is done for the SCs,STs and minorities only, which is unfortunate for the country. Names involved in Swiss banks and Panama scandals, none belongs to these communities. In coal allotment scandals, 2G-spectrum and Raphael, names that were involved were from the upper castes. All universities are headed by the Vice-Chancellors and Professors, controlling the Supreme courts and the high court, are from the upper castesonly and this is the main reason of justice being expensive, delayed and faulty. For the sake of the countryevaluation should be of each and everyone but it has never happened and will never and India will reel under the same situation. It is most unfortunate?

✦✦✦

To save the Constitution and to safeguard Dalits from atrocities, the SC/ST Parisangh is organising a 2 days National Level seminar on 6th and 7th July 2019 at Mavlankar Hall, Constitution Club of India, Near Patel Chowk Metro, New Delhi. Kindly confirm the participation by filling up the form. Delegation fee Rs. 500 for food and accommodation at Dr. Ambedkar Bhawan, New Delhi.

https://bit.ly/2Dn1Dm0

Contact

Sumit Kumar, Mob. 9868978306

Ankit Kumar, Mob. 7827720495

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:

Five years	:	**Rs. 600/-**
One year	:	**Rs. 150/-**

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by Ganesh Yerekar